आप राष्ट्रवादी, हिंदूवादी और उन्मादी हैं तो सरकार, पुलिस, न्यायालय सब आपकी जेब में!

गौहत्या और गौ-मांस के नाम पर लगातार हत्याएं हो रहीं हैं, पर किसी की मजाल है कि हत्यारे पकड़े भी जाएँ। ज्यादा जोर लगाने पर किसी भी बेगुनाह के सर पर हत्या का आरोप लगाकर पुलिस आरोपी को साफ बचा लेती है।

महेंद्र पाण्डेय, वरिष्ठ लेखक

कुछ दिनों पहले ही प्रतिष्ठित लन्दन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में असमानता के अध्ययन के लिए अमर्त्य सेन चेयर की स्थापना की गयी है। अमर्त्य सेन ने आर्थिक और सामाजिक असमानता पर विशेष काम किया है और पुस्तकें भी लिखीं हैं, मगर आर्थिक और सामाजिक असमानता से परे भी और तरीके की असमानता है जिस पर कोई चर्चा नहीं की जाती।

हम तो अपने आजाद देश में भी असमान हैं। न्याय व्यवस्था का उदाहरण तो सबसे सामने है। जब न्यायाधीश पर कोई आरोप लगाता है तो न्याय व्यवस्था ध्वस्त होने लगती है और अरुण जेटली न्यायपालिका के साथ खड़ा होने का समय बताते हैं। पूरी दुनिया ने देख लिया कि हमारी न्याय प्रणाली कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति है जिस पर कोई आरोप लगता है तो पूरी प्रणाली ध्वस्त हो जाती है। दूसरी तरफ करोड़ों लोग इसी प्रणाली में न्याय की आस में पिस रहे हैं, उनके लिए सोचने का समय भी किसी के पास नहीं है।

इस मामले की भी बात करें तो जिसने आरोप लगाया उसे तो अपनी बात कहने के लिए बुलाया भी नहीं गया, और जिस पर आरोप थे वही न्यायाधीश भी थे। मानव के पूरे विकास क्रम में ऐसा वाक्य शायद ही दूसरा हो। कुछ दिनों पहले ही यह खबर आयी थी कि भारतीय जेलों में जितने कैदी हैं उनमें से 66 प्रतिशत के मुकदमे विचाराधीन हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि 66 प्रतिशत कैदी आज की तारीख में गुनाहगार नहीं हैं, फिर भी जेल में बंद हैं।

यही हमारी कानून प्रणाली है, जो केवल

मोदी जी तो चुनाव का दिन हो या इससे पहले का दिन, भव्य रोड शो कर लेते हैं जिसे हरेक समाचार चैनेल पर बार-बार दिखाया जाता है, पूरी दुनिया इसे देखती है पर चुनाव आयोग को यह कभी नहीं दिखता। शिकायत करने पर चुनाव आयोग इन पर कुंडली मार कर बैठ जाता है, और मोदी जी फिर से वही कारनामा दोहराते हैं। चुनाव आयोग तो राष्ट्र के नाम सन्देश भी नहीं देख पाता। पहले तो केवल सीबीआई ही पिंजरे का तोता थी, आज तो सभी संवैधानिक संस्थाएं खुद ही अपने लिए पिंजरा खरीदती हैं और फिर इसमें स्वतः चली गयी हैं।

अमीरों या फिर सत्ता के करीबियों को ही न्याय दिला पाती है। इस कानून व्यवस्था, जिसमें लोगों को न्याय नहीं मिलता या फिर खरीदने पर मिलता है, की बातें कोई न्यायाधीश नहीं करता और न ही अरुण जेटली या कोई दूसरा नेता करता है। क्या इस तरीके की असमानता के लिए भी कहीं कोई अध्ययन किया जाएगा?

ऐसा ही अंतर रिजर्व बैंक भी करता है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में जिस संवैधानिक संस्था में सबसे अधिक गिरावट आई है, वह रिजर्व बैंक ही है। नोटबंदी के समय सभी इसकी औकात से वाकिफ हो गए थे। इतना बड़ा फैसला सरकार ने ले लिया और रिजर्व बैंक यह तक नहीं कह पाया कि इस फैसले का अधिकार केवल उसका है, सरकार का नहीं। उस संस्थान को आप क्या कहेंगे, जहाँ का मुखिया कोई था और नए नोट पर हस्ताक्षर किसी और के छप रहे थे।

नोटबंदी के नाम पर तो मध्यम वर्ग और गरीब के साथ साथ पेशेवर लोग भी और गरीब होते चले गए, पर इसी रिजर्व बैंक की कोई भी ऐसी नीति या घोषणा नहीं होती जिससे धनाढ्यों को कहीं से चोट पहुँचती हो। यह तो सबको मालूम है कि गरीबों का कारोबार चौपट हो गया, पर क्या किसी को मालूम है कि उसी अवधि में अडानी, अम्बानी, टाटा और इसी तरह के धनाढ्यों का कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था, बीजेपी के नेताओं का भी खजाना भर रहा था।

जनता की तो छोड़िये, समानता तो नेताओं में भी नहीं है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह सरीखे नेताओं की चुनावी भाषा में चुनाव आयोग को कुछ भी अजीब नहीं लगता, कभी आचार संहिता की अवहेलना नहीं होती, पर क्या यही वरदान दूसरे नेताओं को भी मिला है?

मोदी जी तो सैनिक, बालाकोट, विपक्षी नेताओं के लिए ओछी भाषा का प्रयोग, हिन्दू-मुस्लिम सभी कुछ कहते हैं और लगातार कहते जा रहे हैं, पर कभी चुनाव आयोग ने कुछ कहा? पर उनकी तुलना में शिष्ट भाषा बोलते दूसरे नेताओं के भाषण पर चुनाव आयोग की भावें तनने लगती हैं। इन नेताओं के लग्जरी चुनावी दौरों पर भी चुनाव आयोग को कोई आपत्ति नहीं होती, वहीं साधारण रोड शो का भी हिसाब पूछा जाता है।

मोदी जी तो खुद गरजकर चौकीदार बन जाते हैं, मैं भी चौकीदार की मुहिम चलाते हैं, भगोड़ों और अपराधियों को चौकीदार बनने की बधाई भी देते हैं, पर कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ चौकीदार चोर है कहने पर जज साहब कोर्ट में पूछते हैं कि चौकीदार कौन है? इसी तरह राफेल मामले में सरकार ने न्यायालय में बहुत कुछ छुपाया और बहुत कुछ गलत बताया पर न्यायाधीश साहब मौन रहे और अंत में गलतियाँ उजागर करने वाले पर ही बरस पड़े।

अमित शाह या फिर बीजेपी के दूसरे बड़े नेता सुनवाई में हाजिर न हों तो न्यायालयों को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अरविन्द केजरीवाल और योगेन्द्र यादव सुनवाई में नहीं जा पायें तो नान-बेलेबल वारंट आ जाता है। साधवी प्रज्ञा कुछ भी बोलें तो चुनाव आयोग को एक श्लोक लगता है, पर सजा मायावती को होती है। समानता तो मुख्यमंत्रियों में भी नहीं है।

केंद्र-शासित प्रदेशों में राज्यपाल के बदले उप-राज्यपाल होते हैं, और फिर मुख्यमंत्री होते हैं। राज्यों में भी मुख्यमंत्री होते हैं। पर दोनों मुख्यमंत्रियों में अंतर तो समय समय पर असहाय और शक्ति-विहीन अरविन्द केजरीवाल बता देते हैं।

आज के दौर में सबसे बड़ा विभाजन राष्ट्रवादी, हिंदूवादी और उन्मादी लोगों और शेष भारत में है। यदि आप राष्ट्रवादी, हिंदूवादी और उन्मादी हैं तो सरकार, पुलिस, न्यायालय सभी आपको बचाते रहेंगे और जरूरत पड़ी तो शिकायतकर्ता को ही दोषी ठहराकर दम लेंगे। कथित तौर पर गौहत्या और गौ-मांस के नाम पर लगातार हत्याएं हो रहीं हैं, पर किसी की मजाल है कि हत्यारे पकड़े भी जाएँ। ज्यादा जोर लगाने पर किसी भी बेगुनाह के सर पर हत्या का आरोप लगाकर पुलिस आरोपी को साफ बचा लेती है।

यदि कभी अति-उत्साही पुलिस वाले असली मुजरिम को पकड़ते हैं, तब ऐसे पुलिस वाले ही मार दिए जाते हैं। असली मुजरिम तो सरकारी संरक्षण में फलते-फूलते रहते हैं और चुनावों में उम्मीदवार बना दिए जाते हैं या फिर मृत्यु के बाद शहीद करार दिए जाते हैं। लन्दन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की अमर्त्य सेन चेयर तो आर्थिक और सामाजिक असमानता का हल खोज लेगी, पर हमारे देश की असमानता पर कौन ध्यान देगा?

आधुनिक पूँजीपतियों का साम्राज्य और वैश्विक लूट

राजेन्द्र रवि

भारत और दुनिया के एक बड़े भूभाग में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए आई थी। आगे चलकर उसी के गर्भ से इन देशों में ब्रिटिश हुकूमत का उदय हुआ। उस काल-खण्ड में ब्रिटिश हुक्मरान अपने द्वारा विकसित किए जा रहे ढाँचागत निर्माण और विकास को स्थानीय लोगों और समाज की उन्नति के लिए अपना योगदान ही कहते थे। उस वक्त की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार अपनी योजनाओं की घोषणा, निर्माण और अमल की सूचनाएँ और जानकारियाँ सार्वजनिक तौर पर टुकड़े-टुकड़े में साझा करती थी ताकि इसके तात्कालिक और दूरगामी परिणामों एवं प्रभावों के बारे में कोई एकीकृत तथा सामूहिक आकलन कर पाना मुश्किल हो और तथाकथित विकास की इन योजनाओं के खिलाफ कोई मुखर प्रतिरोध शुरू न हो जाए। इसके बावजूद धीरे-धीरे अंग्रेजों की यह रणनीति जग-जाहिर होने लगी और इसका संगठित विरोध भी होने लगा। कालांतर में यही विरोध गुलामी से मुक्ति का आन्दोलन बना। उस समय इस आन्दोलन में भारतीय उद्योगपतियों और व्यापारियों का भी खुला सहयोग और समर्थन था।

लेकिन जनता के साथ उनके सहयोग और समर्थन का यह काल बहुत लम्बा नहीं चला। आजादी की एक शताब्दी पूरा होने के पहले ही यहाँ के पूँजीपतियों ने सामूहिक रूप से अपने को ईस्ट इंडिया कंपनी के चाल-चरित्र में रंग लिया ।

इसमें उन्हें देश के शासक और प्रभु वर्ग का भरपूर समर्थन हासिल हुआ। वैश्वीकरण और निजीकरण के इस दौर में

याराना पूंजीवाद के पोस्टर ब्वॉय : पीएम नरेन्द्र मोदी और पूंजीशाह गौतम अडानी

नवउदारवादी राज्य ने सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय अन्याय को चरम पर ला दिया है। हर पूँजीपति की एक सी कहानी है, सिर्फ नाम और खानदान अलग-अलग हो सकते हैं । हम यहाँ झारखण्ड के संदर्भ में एक ख़ास पूँजीपति और उसके सपनों की परियोजना का आकलन करते हुए बात करेंगे। उस पूँजीपति का नाम है गौतम अडानी। इनके पास कम्पनियों का अंबार है, इनकी कम्पनियों का जाल-संजाल विस्तृत है। हर काम के हकदार सिद्ध कर लेते हैं ये। ये हैं भारत के वैश्विक पूँजीपति।

दुनिया के हर उस इलाके में दखल है जहाँ से संसाधनों को लूटा-खसोटा जा सकता है। ऐसी ही लूट-खसोट वाली मेहनत की कमाई से जमा अकूत संपत्ति के कारण इन्हें दुनिया के दस संपत्तिशाली लोगों में गिना जाता है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खदान को येन-केन-प्रकारेण हथियाया है। इसे हथियाने में भारत के प्रमुख सेवक ने अपनी सेवा दी है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अगले 60 वर्ष तक 2.6 बिलियन टन कोयला खनन का अधिकार प्राप्त किया है। यह ऑस्ट्रेलिया के साथ-साथ दुनिया का नंबर एक खनन-क्षेत्र माना जाता है। अडानी यहाँ से कोयला निकाल कर दुनिया के दूसरे हिस्से के साथ-साथ भारत भी लाएँगे। इन्होंने कोयले की आवाजाही सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध बन्दरगाह को अपने अधिकार में लिया है, जो निर्बाध रूप से सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया से आने वाला अधिकांश कोयला भारत में आए। इसकी तैयारी के लिए इन्होंने भारत के कई राज्यों के पुराने बन्दरगाहों पर कब्जा किया है या नए बन्दरगाहों के निर्माण का अधिकार प्राप्त किया है । इन राज्यों में गोवा, गुजरात, आंध्रप्रदेश, केरल और झारखण्ड शामिल हैं। आयातित कोयले का ज्यादा इस्तेमाल वह खुद अपने पॉवर प्लांटों में करेंगे और बाकी दूसरी कम्पनियों को बेचेंगे।

आज दुनिया में कोल खनन और कोयले से पैदा होने वाली ऊर्जा का विरोध हो रहा है और कई देश इसके उपयोग को बन्द कर रहे हैं या प्रतिबंधित कर रहे हैं, क्योंकि इससे पर्यावरणीय ऊष्मा बढ़ती है और जलवायु-परिवर्तन की समस्या पैदा होती है। ऑस्ट्रेलिया कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अडानी के कोल खनन को कानूनी चुनौती भी दी है। अडानी का गोड्डा पॉवर प्लांट इसी वैश्विक पूँजीनिवेश और संसाधन लूट की कड़ी का हिस्सा है और साहेबगंज पोर्ट उस तक पहुंचने का सुगम मार्ग। अडानी की इन दोनों परियोजनाओं का स्थानीय स्तर पर कड़ा प्रतिरोध हो रहा है।

लेकिन झारखण्डी जनता द्वारा चुनी गई सरकार अडानी के आगे-पीछे खड़ी है और उनकी रक्षा में सशस्त्र बल और प्रशासन का पूरा तन्त्र खड़ा है। यही वजह है कि निहत्थी जनता लड़ते हुए अपने को अकेला पाती है। अभी-अभी अडानी के गोड्डा पॉवर प्लांट को झारखण्ड सरकार ने 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' के रूप में मंजूरी दी है। इस विशेष क्षेत्र को मंजूरी देते हुए सरकार ने बहुत ही गर्वपूर्वक कहा, "इस सेज से उत्पादित होने वाली संपूर्ण बिजली का निर्यात पड़ोसी देश बांग्लादेश में किया जाएगा, जिससे इस पूरे इलाके का विकास होगा।" उसने आगे कहा, "अडानी पॉवर प्लांट के विशेष आर्थिक क्षेत्र बनने से अन्य उद्योगों का मार्ग खुलेगा। साथ ही विशेष आर्थिक क्षेत्र के अन्दर लगने वाले उद्योगों पर अगले कुछ सालों के लिए सभी प्रकार के टैक्सों पर छूट होगी और सभी प्रकार की सरकारी सहायता पूर्ववत जारी रहेगी।"

आज झारखण्ड की सरकार देश और दुनिया के पूँजीपतियों के लिए "मोमेंटम झारखण्ड" का मेला लगाती है जहाँ झारखण्ड के संसाधनों की लूट के लिए बोली लगाई जाती है और जो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें राष्ट्रद्रोही घोषित करके जेलों में बन्द कर दिया जाता है। दूसरी ओर आदिवासियों के लिए सुरक्षा कवच बने कानूनों को भी पूँजीनिवेश के नाम पर पूँजीपतियों के हित में बदला जा रहा है।

चौथे 'मोमेंटम झारखण्ड' के लिए पूरे राज्य के साथ-साथ देश के कई दूसरे इलाकों में ऐसा प्रचार-प्रसार किया गया, मानो इससे झारखण्ड के जन-समुदाय का कायाकल्प होने वाला है। राँची की सड़कों को दुल्हन की तरह सजाया और सँवारा गया। ऐसे ही समिट में अडानी ग्रुप ने गोड्डा में 1600 मेगावाट कोयला-आधारित अल्ट्रा-मेगा-सुपर क्रिटिकल पॉवर प्लांट और साहेबगंज में गंगा नदी पर पोर्ट स्थापित करने की घोषणा की। झारखण्ड में लगाई जा रही अडानी की दोनों परियोजनाओं से स्थानीय समुदायों को रत्तीभर भी फायदा नहीं है, जबकि दोनों परियोजनाएँ उन्हीं की धरती पर और उनके ही संसाधनों पर कब्जा कर लगाई जा रही हैं। ये दोनों परियोजनाएँ वैश्विक स्तर पर निगमीकरण का हिस्सा हैं, जिनमें स्थानीय और दूसरे मुल्कों के संसाधनों का दोहन होगा और कार्पोरेट को फायदा ही फायदा।